आईआईई, गुवाहाटी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईएम, शिलोंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 01 जुलाई 2022: पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उद्यमी इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के इंक्यूबेटर और उद्यम सहायता केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस भागीदारी का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता, इंक्यूबेटर और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। प्रबंधन, उद्यमशीलता और कौशल विकास के क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए, संस्थान सहयोग करेंगे और सूचनाओं एवं संसाधनों का आदान-प्रदान करेंगे।

पूर्वोत्तर में सक्षम उद्यमियों को अपने उद्यमों को स्थापित करने और विकसित करने के लिए पर्याप्त धन, बेहतर बुनियादी ढांचे और वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता होती है। यह सहयोग भारत के पूर्वोत्तर में एक स्टार्ट-अप वातावरण बनाने का इरादा रखता है जो एक उद्यमी-सक्षम इकोसिस्टम के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को और सुदृढ़ करेगा, संभावित रूप से निवेशक निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र शिल्पकारों, कारीगरों और संसाधनों से भरा हुआ है जो इसके नागरिकों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं।

श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कहा: *"पूर्वोत्तर में जबरदस्त क्षमता है जिसे अभी खोजे जाने की आवश्यकता है। यह भागीदारी एक ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग करेगी जहां स्टार्टअप और उद्यमी न केवल स्थानीय लोगों को सहयोग और प्रोत्साहन देकर बल्कि उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण, पेशेवर सलाह और एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी तक पहुंच प्रदान करके क्षेत्र में फल-फूल सकें। हमारा उद्देश्य एक उद्यमशीलता सक्षम इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है जो पूर्वोत्तर में नवाचार और विकास को बढ़ावा देता हो।"*

इस पहल पर सहयोग करके, दोनों संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश में बड़े पैमाने पर कौशल विकास को बढ़ावा देने में एक-दूसरे की सामर्थ्य से लाभान्वित होंगे। संस्थान उद्यमशीलता विकास पर प्रमाणित एक साथ पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और इनक्यूबेशन एंड एंटरप्राइज सपोर्ट सेंटर, आईआईएम शिलांग के तहत स्टार्टअप और इनक्यूबेट्स को भी प्रशिक्षित करेंगे। वे इस क्षेत्र में शैक्षिक व्याख्यान, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और अन्य ज्ञान प्रसार कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देंगे। दोनों संस्थान इनक्यूबेट्स और लाभार्थियों के शोध कार्य के लिए

प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, इनक्यूबेशन सेंटर आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। दोनों संस्थानों के संकाय इनक्यूबेशन सेंटर के लिए अनुवीक्षण, प्रशिक्षण, कार्यशाला और मूल्यांकन निर्णायकों का हिस्सा होंगे।

श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, एमएसडीई और सुश्री अनुराधा वेमुरी, संयुक्त सचिव, एमएसडीई, श्री संदेश तिलेकर, निदेशक, एमएसडीई, डॉ. ललित शर्मा, निदेशक, आईआईई गुवाहाटी, और डॉ. डी.पी. गोयल, निदेशक, आईआईएम शिलांग की उपस्थिती में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों में श्री प्रशांत गोस्वामी, एसोसिएट संकाय सदस्य, आईआईई गुवाहाटी, और डॉ संजीव निंगोमबम, केंद्र समन्वयक, ए.पी.जे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस शामिल थे। समझौता ज्ञापन पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। संस्थान का मुख्य लक्ष्य उद्यमशीलता विकास पर विशेष बल देने के साथ छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। आईआईई ने अपनी स्थापना के बाद से 2316 उद्यमशीलता कार्यक्रम तैयार किए, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से 80053 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। संस्थान ने कुल 30874 लाभार्थियों के साथ कई समूहिक विकास परियोजनाएं भी शुरू की हैं। उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में, एनईआरईएस 1.0 (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय उद्यमशीलता और स्टार्टअप), आईआईई ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 सक्षम स्टार्ट-अप और इच्छुक उद्यमियों की सहायता की है।

<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के बारे में</u>

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा कौशल की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, एमएसडीई ने नीति, ढांचे और मानकों को औपचारिक रूप देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल और सुधार किए हैं जैसे: नए कार्यक्रमों और स्कीमों का शुभारंभ; नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन; राज्यों के साथ साझेदारी; उद्योगों से जुड़ाव और कौशल के लिए सामाजिक स्वीकृति और आकांक्षाओं का निर्माण करना। मंत्रालय का उद्देश्य न केवल मौजूदा जॉबों के लिए बल्कि सृजित की जाने वाली जॉबों के लिए भी नए कौशल और नवाचार का निर्माण करने हेतु कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना है।